दैनिक जागरण

हम या तो रास्ता खोज लेंगे या फिर बना लेंगे

राजनीतिक शरारत

यह आपत्ति एक किस्म की राजनीतिक शरारत ही है कि रमजान के महीने में आम चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि निर्वाचन आयोग की ओर से आम चुनाव की घोषणा होते ही कुछ राजनीतिक दलों ने खुद को मुस्लिम समुदाय का हितचिंतक जताने के लिए ही यह कहा कि रमजान के दौरान चुनाव कराना ठीक नहीं। रमजान का माह मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक वैसा ही पावन कालखंड होता है जैसे हिंदू समुदाय के लिए नवरात्र। अब अगर नवरात्र में चुनाव हो सकते हैं तो फिर रमजान में क्यों नहीं हो सकते? यह सही है कि रमजान में मुस्लिम एक खास दिनचर्या का निर्वाह करते हैं, लेकिन इस दौरान वे अपने सारे काम अन्य दिनों की तरह ही करते हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यह मान रखा है कि रमजान के दौरान मुस्लिम अपना काम-धंधा छोड़कर घर बैठ जाते हैं? एमआइएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यह जवाबी सवाल दागकर एक तरह से इन राजनीतिक दलों को शर्मिंदा ही किया कि क्या रमजान के दौरान मुसलमान काम नहीं करते? समझना कठिन है कि चंद राजनीतिक दलों की तरह से कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि रमजान के कारण मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने में परेशानी आ सकती है? कम से कम उन्हें तो यह सामान्य सी जानकारी होनी ही चाहिए कि रमजान का मतलब दैनिक जीवनचर्या को रोक देना नहीं होता। रमजान के दौरान चुनाव कराए जाने पर आपत्ति का तब कोई मूल्य हो सकता था जब ईद या अन्य किसी पर्व के दिन मतदान की तिथि घोषित की जाती। आम तौर पर निर्वाचन आयोग इसका ख्याल रखता है कि किसी बड़े पर्व के दिन मतदान न हो। अतीत में उसने किसी क्षेत्रीय पर्व-महोत्सव के दौरान होने वाले मतदान को टाला भी है। इस बार भी उसने रमजान को ध्यान में रखते हुए इस दौरान किसी शुक्रवार को मतदान की तिथि घोषित नहीं की।

राजनीतिक दलों को यह पता होना चाहिए कि रमजान के दौरान चुनाव अतीत में भी होते रहे हैं और इससे पहले कभी यह सुनने को नहीं मिला कि रमजान में चुनाव नहीं होने चाहिए। बहुत दिन नहीं हुए जब उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा का उपचुनाव रमजान के समय ही हुआ था। क्या तब मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने में दिक्कत पेश आई थी या फिर ऐसा कुछ सामने आया था कि रमजान में मतदान होने के कारण किसी दल विशेष को चुनावी नफा या नुकसान हुआ? रमजान के दौरान चुनाव कराए जाने को लेकर आपत्ति उठाने वालों ने अपनी सांप्रदायिक सोच का ही परिचय दिया है। इसके जरिये उनका एकमात्र मकसद खुद को मुस्लिम समुदाय की परवाह करने वाला दिखाना और इसकी बहाने चुनावी लाभ लेना ही रहा होगा। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने बेतुकी आपत्ति उठाने वालों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि यह नहीं हो सकता कि रमजान के दौरान मतदान हो ही न। बेहतर होगा कि मुस्लिम समुदाय भी इस पर विचार करे कि रमजान के दौरान चुनाव का सवाल उठाने वाले उसके हितैषी हैं या फिर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले?

कर्तव्य और अधिकार

लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं और इसके तहत उत्तराखंड के पांच लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। सियासी दल तो लंबे समय से इसके लिए तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का भाग्यविधाता मतदाता भी इस अवसर के लिए कम बेसब्र नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी-अपनी नीतियों, उपलब्धियों को गिना प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, यह उनका अधिकार भी है, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस नागरिक की ही है, जिसे अपने लिए सरकार चुननी है। उत्तराखंड के राजनीतिक मिजाज पर गौर करें तो भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां ऐसी हैं, जिनका प्रदेश में बड़ा जनाधार है। राज्य गठन के बाद से अब तक हुए तीन लोकसभा चुनावों में अमूमन इन्हीं दोनों पार्टियों के मध्य मुख्य मुकाबला होता आया है। एकमात्र वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव ही ऐसे रहे, जब समाजवादी पार्टी एक लोकसभा सीट हरिद्वार जीतने में सफल रही। अन्यथा पांचों सीटें भाजपा और कांग्रेस में ही बंटती रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की पांचों लोकसभा सीट जीतने में सफल रही। जाहिर है इस बार कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं भाजपा के लिए अपनी पांचों सीटों को बचाना ही एकमात्र लक्ष्य होगा। मत प्रतिशत पर नजर डालें तो पिछले चुनाव में भाजपा 55 फीसद से ज्यादा मत हासिल करने में कामयाब रही, वहीं कांग्रेस को करीब 34 फीसद मतों से संतुष्ट होना पड़ा। इस बार सियासी दलों के पास प्रचाार के लिए अपेक्षाकृत समय भी कम है। सप्ताह भर बाद ही अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। मैदान में खम ठोकने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। इसमें सबसे अहम मौसम है। प्रदेश का ज्यादातर भाग पहाड़ी है और रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर के कई इलाके अब भी हिमाच्छादित हैं। ऐसे में मतदाता तक पहुंचना प्रत्याशियों के लिए इस महासमर में आसान नहीं होगा।

चुनाव में सबको सन्मति दे भगवान

गोपालकृष्ण गांधी

जब चुनाव होते हैं तब हम दिमाग से, ठंडे दिमाग से मतदान देने जाते हैं और आमतौर पर ऐसा करना चाहते भी हैं, लेकिन सामान्यता जब असामान्यता का सामना करती है तब बात कुछ बदल जाती है

हम भारत के लोग समझदार हैं, भावुक भी। हम अक्लमंद हैं, लेकिन दिल के गुलाम भी। हमें बहकाना आसान नहीं। चालाक, दगाबाज कोई हमारे सामने आए तो हम उसे पहचानने में देर नहीं लगाते-निकम्मा आदमी है यह, चतुरनाथ नंबर वन। न जाने कहां से उसको ऐसा तेज दिमाग, ऐसी तिरछी नजर, ऐसी टेढ़ी जुबान मिली। उसकी बातों में कतई मत आना...और जब चतुरनाथ को यह उपाधि लग जाती है, तो बस समझिए कि हमेशा के लिए लग गई। हां, पुराना चतुरनाथ कभी-कभी नए चतुरनाथ की तुलना में कुछ शरीफ या बेचारा लगने लगता है, खासकर तब जब उसके बाल पक गए होते हैं, बोली कुछ कमजोर हो गई होती है, चलने की गति धीमी पड़ गई हो। यह न-बहकने की काबिलियत जो है हमारी वह एक दिमागी काबिलियत या ताकत है। उस ताकत, उस क्षमता के साथ-साथ चलती है बिल्कुल रेल की दो पटरियों जैसी हमारी दूसरी नस्ल, हमारी जज्बाती तबीयत, हमारी भावुकता। हमारा दिमाग सचेत है, धोखा नहीं खाता, लेकिन हमारा दिल कोमल है। उसको हंसाओ, जी खोलकर हंसेगा। रुलाओ, उसके आंसू कभी नहीं रुकेंगे। दिमाग और दिल, चेतना और भावना जब मिलते हैं तो मन बनते हैं, अंग्रेजी में माइंड। मन कहता है, मन मानता है, मन नहीं मानता, मन नहीं करता।

हमारे प्रधानमंत्री का जो विशेष रेडियो प्रोग्राम है मन की बात वह उस ही दिमाग और दिल के संगम, ब्रेन और हार्ट के मिश्रण को संबोधित करता है। हम उनकी बातों से सहमत हों या न हों, यह जरूर मानना होगा कि प्रोग्राम का शीर्षक मन की बात बिल्कुल बढ़िया है। यह शीर्षक कहता है कि जो बात कही जा रही है वह समझ-बूझ कर कही जा रही है, लेकिन वह निजी भी है, जज्बाती- मन से मन तक और साथ ही दिल से दिल तक। उसे दिमाग से सुनना चाहिए और दिल से अपनाना चाहिए। दिल से। खुशी और गम हमारे कुदरत-बख्श, भगवान से प्राप्त घर हैं और उस घर के कई कमरे हैं जैसे बुद्धि, समझ, हंसी, मजाक, खेल, आशा, निराशा, मायूसी, उदासी, गुस्सा, और अवसाद। सामान्यतः हम बुद्धि में रहते हैं, समझ में बसते हैं, लेकिन चौबीस घंटों का दिन जो है, वह पूर्णत सामान्य नहीं होता। उसके कई असामान्य क्षण होते हैं जो हमें बुद्धि-कक्ष और समझ-कक्ष से उठाकर धकेल देते हैं बाकी जज्बाती कमरों में। और वहां हमारा सफर शुरू होता है, उस दो पटरियों पर दिमाग और दिल। चुनावी दौर अब भारत में सामान्य हो गए हैं। वे ऋतु बन गए हैं- वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और इन सबों के बीच पंचवर्षीय ऋतु- निर्वाचन ऋतु। यह हमारी कामयाबी, हमारी उपलब्धि है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और है। हम भारत के मतदाता निपुण हैं, चुनावी प्रणालियों में, उसकी पद्धतियों में। सोलह बार लोकसभा के चुनाव से गुजर जो चुके हैं। इसलिए जब चुनाव होते हैं, तब हम दिमाग से, ठंडे दिमाग से अपना मतदान देने जाते हैं और आमतौर पर ऐसा करना चाहते भी हैं, लेकिन सामान्यता जब असामान्यता का सामना करती है तब बात कुछ बदल जाती है।

अवधेश राजपूत

1952 का प्रथम लोकसभा चुनाव अपूर्व था। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव। स्वतंत्रता संग्राम पर मुहर लग रही थी। देश ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व को दोनों हाथों से बहुमत दिया। 1957 का चुनाव सामान्य था- चलिए, एक बार और नेहरू का दौर! फिर 1962 में- कांग्रेस पर ही मुहर लगेगी, किसी और की नहीं चलेगी। वरीय स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (राजाजी) को यह स्वीकार न था। प्रजातंत्र में विपक्ष, परिवर्तन जरूरी हैं, उन्होंने कहा। उनकी नई स्वतंत्र पार्टी पुराने जमाने के राजाओं और जमींदारों और उद्योगपतियों के समर्थन के साथ कांग्रेस के सामने डटकर खड़ी हुई। कांग्रेस को उस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने अच्छा-खासा झटका दिया, दिमागी झटका। यदि 1962 में चीनी हमला चुनाव के पहले हुआ होता तो चुनाव-परिणाम कुछ और हुआ होता। 1962 का चुनाव परिवर्तनीय बनते-बनते रह गया। जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

1967 का चुनाव पहला चुनाव था, नेहरू-पश्चात! विपक्ष और विशेषकर स्वतंत्र पार्टी को कई सीटें मिलीं! इस बार स्वतंत्र पार्टी का झटका ताकतवर था। इंदिरा गांधी जीतीं सही, लेकिन मुश्किल से। वह सहमीं, संभलीं और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी को रिटर्न झटका देना शुरू किया-राजाओं-महाराजाओं के प्रिवी पर्स रद हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी राशि देने पर रोक लगाई गई। इंदिरा हटाओ का विपक्षी नारा जनता को भाया नहीं। उसके दिमाग को वह अप्रिय लगा। और इंदिरा का जवाबी नारा, गरीबी हटाओ जनता के दिल को छू गया। विजयी बना।

1971 के अगले चुनाव में इंदिरा गांधी को जीतना ही था और जीतीं भी- शान से, मान से। उन्होंने 1971 में अपनी अद्भुत विजय प्राप्त की अपने दिमाग से, धैर्य और साहस से, लेकिन उनको जो विजय मतदाता ने दी, वह अपने दिल से दी। समय जो कि वर देता है, वह कर भी ले लेता है। न जाने क्यों, किस बद-ख्याली में, किस बद-घड़ी में, विजयी इंदिरा का शासन एकाधिपत्य की ओर बढ़ते गया। राजभार ने उनके आंखों पर कई परदे लगा दिए, जो उनके नेताओं के भ्रष्टाचार को भी ढंक रहे थे और उनके पुत्र संजय के तरीकों को भी। इतिहास का यंत्र बनकर और लोकनायक की संज्ञा प्राप्त किए जयप्रकाश नारायण तब उभरे। काश, इंदिराजी उनकी सुनतीं। आपातकालीन स्थिति में क्या हुआ, न हुआ, इसका उल्लेख पाठकों के लिए अनावश्यक है। 1976 में होने वाले चुनाव टाले गए। गलती हुई। जब 1977 में चुनाव हुए, जनता अपने गुस्से-भरे दिल से बोली रामधारी सिंह दिनकर के अल्फाज में- सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इंदिरा गांधी परास्त हुईं।

दिमाग आसानी से बदलता नहीं। दिल चंचल है, बदलता रहता है। जिस इंदिरा गांधी को 1977 में उसने हराया दिल से, उन्हीं इंदिरा को उसने वापस बुलाया 1980 में दिमाग से। और जब इंदिराजी की हत्या हुई तो उनके सुपुत्र राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1984 में जीती, दिल से। आत्मीय श्रद्धा, विश्वास का अभिन्न अंग है। राजीव को श्रद्धांजलि-नुमा विजय मिली। 1989 में 1984 के अति-लोकप्रिय राजीव को जनता ने परास्त किया, दिमाग से। और देखिए दिल-दिमाग का खेल। चुनाव के ठीक मध्य में 1991 में भारत राजीव कांग्रेस को हरा रहा था, बुरी तरह। पर जब चुनाव के ठीक बीच राजीव की दुःखद हत्या हुई तो उसी भारत ने करवट बदली और बाद में हुई वोटिंग में जो कांग्रेस हार रही थी, जीत गई बाकी सीटें बड़ी संख्या में और सरकार बना गई, पीवी नरसिंह राव की।

बाद में हुई चुनाव श्रृंखला से पाठक परिचित हैं। मात्र इतना कहकर यह लेख समाप्त करता हूं- निराशा, मायूसी, अन्याय, अधिकार-अवहेलना, भ्रष्टाचार मतदाता के दिमाग को झकझोरते हैं। ज़ुल्म, हत्या, मृत्यु, युद्ध-ये मतदाता के दिलों में प्रवेश करते हैं। आज के इस क्षण के निर्णय अगले पांच वर्षों को गढ़ते हैं। चुनाव किस संदर्भ में होते हैं या फिर संदर्भ किस चुनाव में बनते हैं, इस पर निर्भर होते हैं उनके परिणाम। सबको सन्मति दे भगवान!

(वर्तमान में अध्यापनरत लेखक राजनयिक और राज्यपाल भी रहे हैं)

response@jagran.com

घर-परिवार का अर्थशास्त्र

डॉ. भरत झुनझुनवाला

स्वतंत्र आय हासिल करने से महिला का सबलीकरण होता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है

महिला और पुरुष का भेद पुरातन है। पहले जीव एक सेल के गैमेट (युग्मक) होते थे। ये एकलिंगीय और केवल एक कोशिका से बने होते थे। इनमें नर और मादा नहीं होते थे। फिर भी दो गैमेट के संयोग से नए गैमेटों का सृजन होता था। बड़े गैमेट अपनी जगह स्थिर रहने लगे, जबकि छोटे गैमेट तेजी से इधर-उधर चलकर उनके साथ जुटने लगे। ये बड़े गैमेट समयक्रम में मादा बने और छोटे गैमेट नर बने। आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शारीरिक दृढ़ता ज्यादा होती है। शायद यही कारण है कि अमेरिका में महिलाओं की औसत आयु 80 वर्ष है, जबकि पुरुषों की औसत आयु मात्र 70 वर्ष है। महिलाएं छोटे बच्चों को इसलिए आसानी से पाल पाती हैं, क्योंकि वे उनसे अचेतन वार्तालाप कर सकती हैं और बातें करते रहना उनके लिए आसान होता है। गणित आदि तार्किक विचारों और संकल्प की पूर्ति में पुरुष ज्यादा निपुण होते हैं। जैसे-जैसे जीवों का विकास होता गया वैसे-वैसे नर और मादा के अंतर बढ़ते गए और आज यह अंतर मनोवैज्ञानिक भी हो गया है। हम यह मान सकते हैं कि जिस प्रकार बीते अरबों वर्षों में यह अंतर बढ़ता गया है, आगे भी यह बढ़ता ही जाएगा।

21वीं सदी के परिवार की संरचना को समझने का दूसरा आधार नई तकनीकें हैं। बिजली से जलने वाले बल्ब एवं बिजली से ही चलने वाली मिक्सी और वाशिंग मशीन, पाइप से आने वाला पानी, गैस से चलने वाले स्टोव आदि उपकरणों से घरेलू कार्य सरल हो गए हैं। पहले परिवार चलाने के लिए एक व्यक्ति को पूरा समय इन कार्यों को करने के लिए देना पड़ता था। अब ये कार्य घंटे दो घंटे में संपन्न हो जाते हैं। इसलिए महिला के लिए अब पर्याप्त समय दूसरे कार्यों के लिए उपलब्ध हो गया है।

21वीं सदी के परिवार की संरचना हमें इन दोनों कारकों के बीच खोजनी है। एक यह कि महिला और पुरुष के बीच अंतर बढ़ता जाएगा और दूसरा यह कि गृह कार्य के लिए एक व्यक्ति को अपना पूर्ण समय देना अब जरूरी नहीं रह गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज के प्रचलित परिवार के नए ढांचे के सुझावों का आकलन कर सकते हैं। एक सुझाव है कि महिला और पुरुष गृह कार्य में बराबर का योगदान करें जैसे भोजन पकाने अथवा कपड़ा धोने के लिए। यह महिला और पुरुष अथवा नर और मादा के बीच बढ़ते अंतर के ऊपर बताए सिद्धांत के विरुद्ध बैठता है। अरबों वर्षों की जीवों की यात्रा बताती है की नर और मादा का अंतर बढ़ता गया है। एक कोशिका वाले गैमेट में केवल आकार या वजन का अंतर था। पौधों में केवल फूल के आकार में अंतर होता है। मनुष्य में मनोवैज्ञानिक अंतर भी हो गया है। आने वाले समय में यह अंतर बढ़ेगा। इसलिए पुरुष और स्त्री के कार्यों में भी अंतर बढ़ेगा। दोनों घर का बराबर काम करें, यह नहीं चलेगा।

दूसरा सुझाव है कि महिला अर्थोपार्जन करे। तमाम अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि स्वतंत्र आय हासिल करने से महिला का सबलीकरण होता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है, लेकिन दूसरे अध्ययनों से यह भी पता लगता है कि पूर्णकालिक कार्य करने वाली महिला पर दोहरा वजन आ पड़ता है। कनाडा के परिवारों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि पूर्णकालिक कार्य करने वाली महिलाएं 25 मिनट कम सो पाती हैं। इसलिए यह सुझाव गृह कार्य से मुक्ति के ऊपर बताए गए सिद्धांत के विरुद्ध बैठता है। इस सुझाव में महिला को गृह कार्य तो कम करना पड़ता है, लेकिन कम गृह कार्य को पूर्णकालिक कमाई के साथ करने से उसके ऊपर कुल कार्य का वजन पड़ता है। इसलिए ये दोनों सुझाव मानव विकास की मूल धारा के विपरीत हैं और ये लंबे समय तक चल पाएंगे ऐसा नहीं लगता है।

प्रश्न है कि इन सुझावों के असफल होने के बावजूद इन्हें क्यों बढ़ाया जा रहा है। ऐसा समझ आता है कि महिला और पुरुष के बीच बराबरी की बात छेड़कर समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता से हमारा ध्यान हटा दिया जा रहा है। जिस प्रकार एक चतुर बंदर ने दो मूर्ख बिल्लियों की लड़ाई के बीच उनकी रोटी चट कर ली थी अथवा जिस प्रकार एक चतुर उद्यमी दो ट्रेड यूनियनों को आपस में लड़ाकर लाभ कमाता है उसी प्रकार महिला और पुरुष को घर के अंदर बराबरी का मंत्र देकर समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता से हमारा ध्यान हटा दिया जा रहा है। हर वर्ष समाचार छपते हैं कि देश में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती असमानता के ऊपर तनिक भी सामाजिक हलचल नहीं होती, क्योंकि समाज ने परिवार के अंदर महिला और पुरुष के बीच बराबरी हासिल करने को प्राथमिक बना दिया है और समाज में गरीब और अमीर के बीच बढ़ती असमानता को छिपा दिया है ताकि अमीरों की बढ़ती आय से समाज का ध्यान हट जाए।

ऊपर दिए गए दोनों कारकों को देखते हुए आने वाले समय में परिवार का रूप दूसरा बनाया जा सकता है। वह यह कि महिला को पार्ट टाइम कार्य के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। साथ में उसके द्वारा किए गए गृह कार्य को सम्मानित किया जाए। ऐसा करने से महिला और पुरुष का जो बढ़ता अंतर है वह उपयोगी सिद्ध होगा। महिला की बच्चों को पलने की जो शक्ति है उसका समाज को भरपूर लाभ मिलेगा। महिला बच्चों के पालन में उनकी मनोवैज्ञानिक परवरिश कर सकेगी। साथ-साथ पार्ट टाइम कार्य करने से महिला का आर्थिक सबलीकरण भी होगा। उसके ऊपर दोहरा बोझ भी नहीं आएगा। मेरे एक जानकर मित्र की पत्नी ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करती हैं। बच्चे पैदा होने के दो साल बाद तक उन्होंने सप्ताह में केवल दो दिन कार्य किया, शेष पांच दिन उन्होंने अपने बच्चों और घर को समर्पित किया। ऐसा करने से उनका आर्थिक सबलीकरण भी हुआ और उन पर कार्य का दोहरा बोझ भी नहीं पड़ा। हमें इस पर विचार करना होगा कि महिलाओं के लिए सुलभ समय और दिन के कार्य के अवसर प्रदान करें। जैसे गार्ड का कार्य आठ घंटे की जगह चार घंटे की शिफ्टों में किया जा सकता है अथवा महिलाओं को सप्ताह में दो या तीन दिन कार्य करने और इतने ही दिन अवकाश लेने की सुविधा दी जा सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन से महिला और पुरुष का जो मनोवैज्ञानिक अंतर है उसका समाज को लाभ मिलेगा और नई तकनीकों से महिला का वास्तविक सबलीकरण होगा न कि उसे दोहरे बोझ से लाद दिया जाएगा।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दृष्टि परिवर्तन

प्रत्येक देश शांति चाहता है, सुख चाहता है और इसके लिए पूरा जीवन प्रयास भी करता है। चिंतनीय बात यह है कि मानव तनाव से ग्रसित क्यों है? सुख-दुख जीवन के दो पहलू हैं, जो हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं और इन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। इसके बिना हमारी मुक्ति संभव नहीं। छोटी-सी जिंदगी में भी तनाव हमारा हमसफर बन गया है। इससे छुटकारा पाने के लिए 'दृष्टि परिवर्तन' आवश्यक है। आज हमारी दृष्टि दूसरों के दोष-दर्शन की हो गई है और अपने दोष हमें दिखाई नहीं देते। जगत में कोई भी वस्तु या जीव ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है, पर हमारी दृष्टि बुराइयों पर ही जाती है। हीरा कोयले की खदान में ही मिलता है। उसकी कीमत खदान की कीमत से कई गुना अधिक होती है। तनावमुक्त होने के लिए दृष्टि परिवर्तन करके यह विचार मन में स्थिर करना होगा कि दुखी होने के लिए मैं और मेरे कर्म जिम्मेदार हैं, पर दुखी होने का कारण अन्य को मानते हैं। दृष्टि बदलेगी तो दृश्य बदलते देर नहीं लगेगी। तनाव के बादल छंट जाएंगे, आत्मा आनंदित हो उठेगी। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां तो जीवन के साथ आती-जाती रहती हैं। जब कर्म का बंधन जीवन के परिणामों पर निर्भर है तो कोई अन्य हमें सुखी या दुखी कैसे कर सकता है? भगवान के पथ का अनुसरण, उनकी वाणी पर श्रद्धा और तदनुरूप आचरण ही कृत कर्मों से मुक्ति दिला सकता है। दृष्टि में हित-चिंतन एवं धर्म को स्थान देना चाहिए। सभी जीवात्मा परमात्मा का अंश हैं, यह मानते हुए हिंसा से दूर रहना चाहिए। आत्मा का उत्थान ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।

आत्मिक शांति के लिए धर्म कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है और कालचक्र का पहिया निरंतर मुंह बाए खड़ा रहता है। इसीलिए जो करना है आज ही करना है। अपने जीवन की दिशा सही कर लो, गुणों का संचय करो और माया का त्याग करो। पर-दोष दर्शन न कर आत्मा को निर्मल बनाओ। पृथ्वी पर वपन किया बीज तभी अंकुरित होता है जब उसे जल की शीतलता के साथ सूर्य की ऊष्मा भी प्राप्त हो। इसीलिए दृष्टि परिवर्तन की साधना के लिए अनुकूलता की शीतलता के साथ प्रतिकूलता की ऊष्मा भी आवश्यक है।

बीना जैन

घपलेबाजों का सुरक्षित ठिकाना

फिर से

भारत को नुकसान पहुंचाने वाले दो ही हैं, पहले घपलेबाज और दूसरे आतंकी। और इन दोनों ही मामलों में भारत मजबूर है

पीएनबी में 13000 करोड़ रुपये का घोटाला करके फरार कारोबारी नीरव मोदी लंदन में है। जैसा कि भगोड़े किया करते हैं, नीरव ने भी अपना हूलिया बदल लिया है ताकि लोगों की नजरों में न आ सके। ललित मोदी और विजय माल्या के बाद भारत से घोटाला करके भागा नीरव भी इंग्लैंड में ही छिपा हुआ है। ये ही नहीं भारत के 5,500 से ज्यादा लोगों ने 2013 से ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी हुई है, हालांकि ये सभी अपराधी नहीं हैं। असल में यूके में कड़े मानवाधिकार नियम हैं। मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन में वह एक हस्ताक्षरकर्ता है-जिसके मुताबिक अगर यूके की अदालतों को पता चलता है कि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को यातना या मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा या प्रत्यर्पण राजनीतिक कारणों से हो रहा है तो वे प्रत्यर्पण अनुरोध से इन्कार कर सकते हैं।

वहां प्रत्यर्पण प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। भारत विजय माल्या समेत 9 अपराधियों के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध लगा चुका है, लेकिन ये सभी अभी तक लंबित हैं। यूके ने अभी तक 2016 में केवल एक भारतीय का प्रत्यर्पण किया है, वह है समीरभाई विनूभाई पटेल। यूके ने अब तक भारत द्वारा लगाए गए कई प्रत्यर्पण अनुरोधों को किसी न किसी आधार पर रिजेक्ट किया है। और इसी वजह से भारत से भागे हुए लोग खुद को ब्रिटेन में सुरक्षित महसूस करते हैं।

नीरव को लंदन की सड़कों पर बाखौफ घूमता देख भारत हैरान भी है और परेशान भी। और इसीलिए सरकार से फिर से सवाल किए जाने लगे हैं कि इन भगोड़ों को लेकर सरकार इतनी सुस्त क्यों है? इस पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि हम नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। लंदन में वह दिखाई दिया इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको तुरंत भारत ले आएंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, जो हम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईडी और सीबीआइ से मिली जानकारी के आधार पर पिछले साल अगस्त में ही ब्रिटेन से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था, क्योंकि सरकार जानती है कि वह वहीं है। ब्रिटेन को लेकर तो भारत मजबूर है, पर भारत में रहकर सरकार जो कुछ भी कर सकती है वह कर रही है। यहां उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को ही रायगढ़ जिले के अलीबाग में बीच पर बने नीरव मोदी के एक बंगले को सरकार ने डायनामाइट से उड़ा दिया। अभी तक भारत और विदेशों में मौजूद नीरव मोदी की करीब 1725 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा नीरव मोदी समूह से संबंधित करीब 490 करोड़ रुपये के सोने, हीरे, बुलियन, आभूषण और अन्य कीमती सामान भी जब्त किए गए हैं।

भारत को नुकसान पहुंचाने वाले दो ही हैं पहले घपलेबाज और दूसरे आतंकी। और इन दोनों ही मामलों में भारत मजबूर है, क्योंकि आतंकियों को पनाह देता है पाकिस्तान और घपलेबाजों को ब्रिटेन। पर सवाल अब भी वही है कि विदेशी मामलों में तो सरकार के हाथ बंधे हैं, लेकिन घर के अंदर ही जब ये खेल खेला जा रहा होता है तब ही सरकार कुछ क्यों नहीं कर पाती? शायद इसका जवाब सरकार न दे पाए।

(आइचौकडॉटइन से साभार)

मेलबाक्स

अनियोजित निर्माण के खतरे

दोहरे लाभ वाला कारगर कदम शीर्षक से लिखे अपने आलेख में जीएन वाजपेयी ने माना है कि कंस्ट्रक्शन में तेजी से रोजगार सृजन के साथ ही सभी के लिए घर की जरूरत का राष्ट्रीय सपना भी साकार होगा। मेरा लेखक से यह सवाल है कि देश में अगर इसी तरह कंक्रीट के अनियोजित जंगल बढ़ते गए तो क्या यह पर्यावरण के लिए उचित होगा? लेखक कंस्ट्रक्शन के साथ पर्यावरण को संभालने के भी कुछ उपाय बताते तो अच्छा होता। प्रत्येक सरकार का मकसद देश के नागरिकों को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार उपलब्ध करवाना होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे ये मकसद भी पूरे हो जाएं और पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे। आज देश के लगभग सभी शहरों में गांवों से रोजी-रोटी की तलाश में लोगों के पलायन में आई तेजी, बढ़ती आबादी और परिवारों के टूटने के कारण शहरों के आसपास के खाली क्षेत्रों या खेतों में अनियोजित कालोनियां बनाई जा रही हैं। अगर इस समस्या पर समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई गई तो वह दिन दूर नहीं, जब प्रकृति सौंदर्य के धनी देश में प्रदूषण के कारण जीना मुश्किल जाएगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

चुनाव से गायब पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा

अब दिल्ली उस दौर में पहुंच रही है जब लोगों के लिए स्वच्छ हवा में सांस पुरानी बात लगने लगेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 15 शहर भारत के हैं और इसमें दिल्ली भी शामिल है। यह आंकड़ा बहुत ही चिंता का विषय है। हम सब जहरीली हवा के साथ जी रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कि चुनावों में भी पर्यावरण को बचाने का मुद्दा गायब है। कोई भी दल इस पर ध्यान नहीं देना चाहता तथा इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता है। इसका कारण है कि यह विषय वोट नहीं दिला सकता है। लेकिन हर व्यक्ति एवं अन्य जीव के लिए यह जरूरी है। सरकारें राज्य की हो या केंद्र की सबको इसे गंभीरता लेना चाहिए। वैसे जो हाल हमने अपने पर्यावरण का किया है उसको ठीक करने का दायित्व भी हमारा ही है। अगर यह हाल 2019 में है तो आने वाले 10 -20 वर्षों में क्या होगा? यह बात चिंतित करने वाली है। हर व्यक्ति को भी इस पर चिंतन-मनन करने की जरूरत है। आज हम पर्यावरण को दूषित करने में क्यों तुले हुए हैं? इसे सुधारने की जिम्मेदारी सबकी है। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का तापमान बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी गर्म होती जा रही है, स्वच्छ हवा-पानी बचा नहीं। अगर यही परिस्थिति रही तो आने वाले वर्षों में मानव जीवन को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से हम सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा तभी हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे और उन्हें स्वच्छ जीवन दे पाएंगे। पर्यावरण को सुधारने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो उसे किया जाना चाहिए। भला इससे भी महत्वपूर्ण कोई काम हो सकता है। साफ हवा रहेगी तभी हम सब रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने काम समय पर और सही तरह से कर पाएंगे।

आशीष, राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विवि

गौरैया संरक्षण की अनदेखी

आम लोगों में गौरैया के प्रति ममत्व के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति कितने घोसले बना सकता है? यही कोई 500 या 1000 तक, मान लिया जाए कि इस देश की आबादी सवा अरब है। इसमें से एक प्रतिशत लोग भी गौरैया को बचाने की ठान लें तो विभिन्न स्थानों पर लाखों-करोड़ों की संख्या में नए घोसले और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। यह बहुत बड़ी बात होगी। यह जरूरी है, क्योंकि शहरीकरण के कारण गौरैया की प्रजाति लुप्त हो रही है। इस घरेलू चिड़िया के रहने, खाने-पीने के साधन नष्ट हो रहे हैं। इन्हें बचाना जरूरी है।

निर्मल कुमार शर्मा, प्रतापविहार, गाजियाबाद

गंगा की सफाई की जिम्मेदारी

गंगा की सफाई के लिए न जाने कितने वादे किए गए और योजनाएं बनीं, लेकिन अब तक इसमें कोई सुधार नजर नहीं आया है। बल्कि दिनों दिन इसमें गंदगी बढ़ती जा रही है। यह कोई मुश्किल काम भी नहीं है। सरकार चाहे तो गंगा साफ हो सकती है। बशर्ते शहरों के नालों के पानी को गंगा में जाने से रोक दिया जाए। सरकार को समझना होगा कि केवल योजनाएं बनाने से गंगा साफ नहीं होगी। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी और साफ भावना से काम भी करना होगा।

संध्या, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विवि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं न हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय